View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

brought to you by CORE

provided by Population Council: Knowledge Commons

Population Council
Knowledge Commons

Poverty, Gender, and Youth

Social and Behavioral Science Research (SBSR)

2017

Ensuring adolescents in Uttar Pradesh stay—and learn—in school [Hindi]

Sapna Desai
Population Council

Neelanjana Pandey
Population Council

Follow this and additional works at: https://knowledgecommons.popcouncil.org/departments_sbsr-pgy

Part of the Demography, Population, and Ecology Commons, Education Commons, Family, Life Course, and Society Commons, and the International Public Health Commons

Recommended Citation

Desai, Sapna and Neelanjana Pandey. 2017. "Ensuring adolescents in Uttar Pradesh stay—and learn—in school," Policy brief. New Delhi: Population Council. [in Hindi]

This Brief is brought to you for free and open access by the Population Council.

Policy Brief
Uttar Pradesh

December 2017

किशोरों का स्कूलों में बने रहने और पढाई करते रहना को सुनिश्चित करना

परिप्रेक्ष

भारत सरकार ने दो मुख्य कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से निवेश किया है। यह दो कार्यक्रम हैं ''सर्व शिक्षा अभियान'' जिसे 2001 में प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) के लिए स्थापित किया गया और ''राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान'' जिसे 2009 में शुरू किया गया ताकि विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच मिले और वह अपनी पढ़ाई जारी रखें। राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा प्राप्ति के स्तरों में बढ़त हुई है और उन बच्चों का अनुपात कम हुआ है जो कभी स्कूल नहीं गए। (1) उत्तर प्रदेश में, पापुलेशन कौंसिल ने पाया कि कम उम्र के किशोरों में पंजीकरण का स्तर ऊँचा था, और लड़के और लड़कियों के बीच असमानताएं कम थीं। 10–14 वर्ष के बच्चों में 91% लड़के और 86% लड़कियां स्कूल में पंजीकृत थे।[2] (2) लेकिन प्राथमिक शिक्षा के बाद काफी सारे बच्चे स्कूल आना छोड़ देते हैं, अधिकांश रूप से कंवारी लड़कियां और लड़के स्कूल में केवल नौ वर्ष तक रहते हैं, और शादी–शुदा लड़कियां आठ वर्ष तक। आगे, साक्षरता और अंकों की पहचान में सीख के नतीजे अच्छे नही थे, जिससे शिक्षा के स्तर पर प्रश्न–चिन्ह खड़ा होता है। यह नीति संक्षेप दो मुख्य चुनौतियों पर प्रकाश डालती है ताकि उत्तर प्रदेश के किशोरों का भविष्य उज्जवल हो:

- सम्पूर्ण पंजीकरण और माध्यमिक शिक्षा में बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहन देना
- सीख के नतीजों में सुधार लाना।

मुख्य निष्कर्ष

- प्राथमिक स्कूल में अधिक पंजीकरण के बावजूद, माध्यमिक शिक्षा में पंजीकरण कम था। 15–19 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों में तीन में से दो लड़के, अविवाहित लड़कियों में 2 में से एक और शादी–शुदा लड़कियों में 20 में से एक स्कूल में पंजीकृत थे।
- 55–62% किशोर (15–19 वर्ष) वर्तमान में निजी स्कूलों में पंजीकृत थे।
- स्कूल में बच्चों की उपस्तिथि कम थी: अविवाहित लड़के–लड़कियों में केवल 2 में से एक और शादी–शुदा लड़कियों में केवल 3 में से एक नियमित रूप से स्कूल जा रहे थे।
- अविवाहित किशोरों में (15–19 वर्ष) जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली थी, 5 में से 4 लड़के और लड़कियां कक्षा 2 की किताबें पढ़ पा रहे थे, जबकि 2 में से 1 लड़का और 3 में से एक लड़की सरल भाग (विभाजन) की प्रक्रिया करने में सक्षम थे।
- राज्य के लिए अभी भी अवसर है कि वह स्कूल में मूलभूत सुविधाओं को सुधारे, शिक्षा के स्तर को सुधारे और माध्यमिक शिक्षा में पंजीकरण करने, स्कूल जाने और शिक्षा पूरी करने में जो आर्थिक और सामाजिक बाधाएं आती है, उन्हें हटाए।

उदया अध्ययन

Understanding the lives of adolescents and young adults ('किशोरों और युवावस्था के जीवन को समझना' (उदया) एक ऐसा शोध कार्यक्रम है जिसे पॉपुलेशन कौंसिल ने संचालित किया, यह किशोरों (10–14 वर्ष) और उनसे थोड़े बड़े किशोरों (15–19 वर्ष) की परिस्तिथियों को जानने की कोशिश करता है, उनकी परिस्तिथियों में बदलावों, उनकी जरूरतों का विवरण करता है और उन कारकों का आंकलन करता है जो यह निर्धारित करते हैं कि वह कैसे किशोरावस्था से युवावस्था में परिवर्तन करते हैं। उत्तर प्रदेश में, इस अध्ययन में एक बड़ी जनसंख्या को सर्वे का हिस्सा बनाया गया, और गुणवत्ता का उप–अध्ययन किया गया। 2015–16 में, पॉपुलेशन कौंसिल ने अविवाहित लड़कियों और लड़कों (10–14 वर्ष और 15–19 वर्ष) और विवाहित लड़कियों (15–19 वर्ष) का साक्षात्कार किया। 2018–19 में हम इस समूह का पुर्न–साक्षात्कार करेंगे, जब वह 13–17 और 18–22 वर्ष के होंगे, और अविवाहित लड़कों और लड़कियों (10–14 वर्ष और 15–19 वर्ष) और विवाहित लड़कियों (15–19 वर्ष) के नए आंकड़े लेंगे। यह संक्षेप इस सर्वे के आंकडो के गहन विश्लेक्षण और 2015–16 की विस्तृत समीक्षाओं को पेश करता करता है। इस सर्वे में 10,161 किशोर शामिल थे।

POPULATION COUNCIL
Ideas. Evidence. Impact.

UDAYA
TOWARDS ADULTHOOD

माध्यमिक शिक्षा: पंजीकरण, उपस्थिति और शिक्षा पूर्ण करना।

तकरीबन 3 में से 2 अविवाहित लड़के और 2 में से 1 अविवाहित लड़की (15–19 वर्ष) वर्तमान में स्कूल में पंजीकृत हैं, और स्कूल छोड़ने वालों में लड़कियों का अनुपात अधिक है (Table 1) केवल 5% शादी–शुदा लड़कियां स्कूल में पंजीकृत थीं– अधिकांश ने स्कूल छोड़ दिया था 69%) या कभी स्कूल में थी ही नहीं (21%)। लड़कों का स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण था पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होना या फिर पैसा कमाने वाला काम करना। अविवाहित लड़के और लड़कियों की लिए घर का काम, आर्थिक कारण, माता–पिता का इस ओर ध्यान नहीं देना और यातायात/स्कूल का दूर होना मुख्य कारण थे जिनके कारण उन्होंने स्कूल छोड़ा।

स्कूली सुविधाएँ– पीने योग्य पानी की उपलब्धता, शौचालय, खेल का मैदान और पुस्तकालय– यह सब ठीक–ठाक हाल में थे। 15–19 वर्ष की आयु के तकरीबन सभी विद्यार्थियों ने कहा की पीने का पानी उपलब्ध है, और 5 में कम–से–कम 4 ने कहा कि उनके वर्तमान स्कूल में शौचालय की स्थिति भी ठीक थी। स्कूल में तीन–चौथाई से अधिक लड़कियों ने रिपोर्ट किया कि उनके स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय था। अधिकांश लड़के और लड़कियों के लिए खेल के मैदान भी उपलब्ध थे, जबकि पुस्तकालय कुछ कम थे। कुल मिलाकर, 36% लड़के और 40% से कुछ अधिक अविवाहित और विवाहित लड़कियों ने कहा कि वह ऐसे स्कूल में हैं जहाँ यह चारों सुविधाएँ प्राप्त हैं, और सरकारी और निजी स्कूलों के बीच कोई विशेष फर्क नहीं था।

Table 1: Current schooling status, adolescents 15-19 years

Current schooling	Unmarried boys (15-19)	Unmarried girls (15-19)	Married girls (15-19)
% currently in school	63.4	52.2	5.2
% in distance education	4.2	5.5	5.3
% dropped out	28.3	35.4	68.6
% never enrolled	4.1	6.9	20.9
Total	**2,064**	**4,338**	**1,798**

स्कूल में उपस्तिथि नियमित रूप से नहीं होती। करीब आधे बड़े लड़के और लड़कियों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने पिछले सप्ताह एक दिन स्कूल से छुट्टी ली (Figure 1)। स्कूल नहीं जाने के मुख्य कारण थे घरेलु जिम्मेदारियाँ, दिलचस्पी नहीं होना, आर्थिक मजबूरियां और बीमारी। सरकारी स्कूल या निजी स्कूल में उपस्तिथि के मामले में विशेष अंतर नहीं था।

Table 2: Leading reasons for not attending school regularly amongst adolescents, 15-19 years

Reason reported	Unmarried boys (15-19)	Unmarried girls (15-19)	Married girls (15-19)
Paid work	32.7	10.1	3.4
Did not want to attend	15.5	20.2	26.3
Respondent's illness	13.5	19.2	6.8
Domestic chores	22.5	23.1	31.9
Lack of transport	4.6	12.2	15.7

Figure 1: Attendance patterns amongst unmarried adolescents, 15-19 years

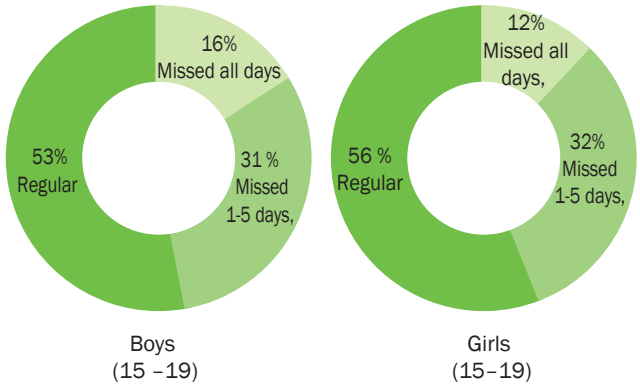

शिक्षा की प्राप्ति और स्कूल के उच्चतम स्तर की प्राप्ति प्राथमिक शिक्षा पाने के बाद लगातार घटती है (Figure 2) जबकि शुरुआती कमी प्राथमिक शिक्षा के पांच साल बाद आती है, सबसे अधिक कमी आंठवी कक्षा के बाद आती है–लड़के और लड़कियां दोनों के लिए। शादी–शुदा लड़कियां छोटी कक्षाओं में ही स्कूल छोड़ देती हैं और अविवाहित लड़कियों के मुकाबले उनकी पढाई कम स्तर तक होती है।

लड़कों ने स्कूल छोड़ने के कारणों में– पढ़ाई में दिलचस्पी की कमी होना या परिवार के कामों में 'शामिल होना या? घर से बाहर काम करना प्रमुख कारण बताये। लड़कियों ने स्कूल छोड़ने के लिए मुख्य कारणों में– घरेलू कारण जैसे आर्थिक असामर्थ्य, घर के काम, परिवार का पढ़ाई को कम प्राथमिकता देना और स्कूल का दूर होना बताया।

Figure 2: Cumulative percentage of adolescents (15-19) who had completed each year of education, 2015-16

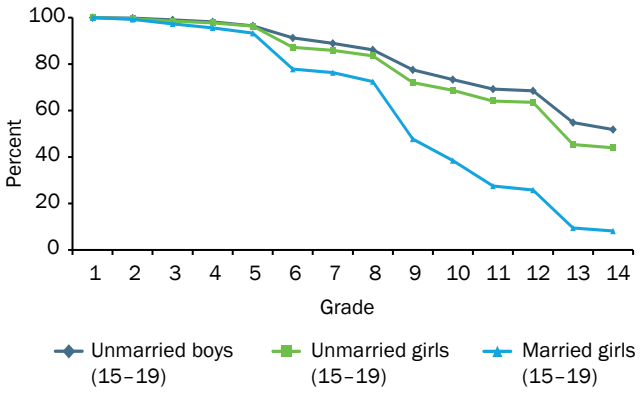

माध्यमिक शिक्षा में पंजीकरण और शिक्षा लेते रहने के कारक[1]

■ परिवार का परिप्रेक्ष्य: सामाजिक–आर्थिक स्थिति और माता–पिता की शिक्षा।

वह परिवार जो आर्थिक रूप से संपन्न थे वह अपने बेटे और बेटियों को स्कूल भेजते ही हैं। यदि किशोर लड़कियों की बात करें तो देखते हैं कि यदि उनके माता–पिता ने कम–से–कम दस वर्ष की शिक्षा प्राप्त करी है तो अधिक सम्भावना होती है कि वे भी इतनी शिक्षा लें।

स्कूल में मूलभूत सुविधाएँ

वह किशोर जो ऐसे स्कूल में पंजीकृत थे जहाँ सभी चार सुविधाएँ उपलब्ध हैं (पीने का पानी, शौचालय, खेल का मैदान और पुस्तकालय) उनकी अधिक सम्भावना होती है कि वह स्कूल आते रहें, उनकी तुलना में जो कभी स्कूल में थे, लेकिन बीच में छोड़ दिया।

पैसा कमाने वाले काम में लगे हैं

काफी भारी अनुपात में ऐसे किशोर हैं जो पैसा कमाने का काम करते हैं: 41% लड़के, 25% अविवाहित लड़कियां और 22% शादी–शुदा लड़कियां। इस कार्य में संलग्न होने का अर्थ है की उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, पैसा कमाने के अवसर को देखते हुए और अन्य कारणों से।

सीख के नतीजे

उदया के परिणाम शिक्षा के स्तर की कमियों को उजागर करते हैं। अधिकांश किशोरों के लिए, हिंदी में पढ़ पाने की क्षमता और गणित में विभाजन करने की क्षमता जो होनी चाहिए उससे बहुत कम थी। (Figure 3) अविवाहित किशोरों के लिए जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा या उससे ऊँची शिक्षा पूरी कर ली थी, 83% लड़के, 81% अविवाहित लड़कियां और 65% शादी–शुदा लड़कियां कक्षा 2 की किताब पढ़ने में सक्षम थीं– और यह नतीजे उनसे निचली कक्षाओं में पढ़ने वालों के लिए और भी खराब थे (Figure 4)। आगे, 53% लड़के, 32% अविवाहित लड़कियां और 13% शादी–शुदा लड़कियां (15–19 वर्ष) जिन्होंने कम से कम 8 स्तर की शिक्षा पूरी कर ली थी, वह विभाजन का सरल प्रश्न हल कर पा रहे थे। यह स्तर अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग थे। सरकारी स्कूलों में पढ़े 44% लड़के और 24% लड़कियां जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी की थी वह पढ़ने और लिखने में सक्षम थे, लेकिन निजी स्कूलों में पढ़ने वालों का अनुपात अधिक था–56% लड़के और 37% लड़कियां।

सीख के नतीजों के कारक

निजी ट्यूशन

जनसांख्यिकी की विषेशताओं, निजी स्कूल/सरकारी स्कूल की सुविधाओं और उपस्तिथि को समन्वित करने के बाद यह पता चला कि पिछले महीने में लिया गया निजी ट्यूशन विद्यार्थी के बेहतर प्रदर्शन में सहायक होता है–उनके पढ़ने की क्षमता और विभाजन करने की क्षमता में– जिससे यह पता चलता है कि ट्यूशन से फर्क पड़ता है क्यूंकि इससे बच्चों को बेहतर समझ में आता है। न ही स्कूल का निजी या सरकारी होना, और न ही स्कूल में दी जाने वाली सुविधाएँ अपने आप में कोई कारक हैं जिनसे सीख के नतीजे प्रभावित होते हैं।

लड़कियों के सम्बन्ध में उनके परिवार का आर्थिक स्तर और उनकी माताओं की शिक्षा का प्रभाव

लड़कियों के नतीजे उनके परिवार के आर्थिक स्तर से जुड़े थे। और वह लड़कियां जिनकी माताओं ने कम से कम आठ साल की पढाई करी थी वह पढ़ पाने और विभाजन कर पाने में औरों से दो गुना अधिक सक्षम थीं। पिता की शिक्षा का स्तर न तो लड़कियों, न लड़कों के सीख के नतीजों को प्रभावित करता हुआ पाया गया।

लिंग की असमानताओं की समीक्षा

शिक्षा के करीब हर क्षेत्र में लड़कियां लड़को से पीछे थीं, केवल स्कूल में उपस्तिथि के अलावा। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियां लड़कों से अधिक संख्या में स्कूल छोड़ती हैं। हालाँकि अविवाहित लड़कों और लड़कियों में सीख के नतीजों में अधिक अंतर नहीं था, आंकड़ों के मामले में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से काफी कम था। ऐसा लगता है परिवार लड़कियों की शिक्षा में कम निवेश करते हैं: निजी स्कूलों में कम लड़कियां पंजीकृत थीं, और लड़कों के मुकाबले वह निजी ट्यूशन भी कम प्राप्त कर रही थीं।

Figure 3: Ability to solve basic division, by grades completed[ii]

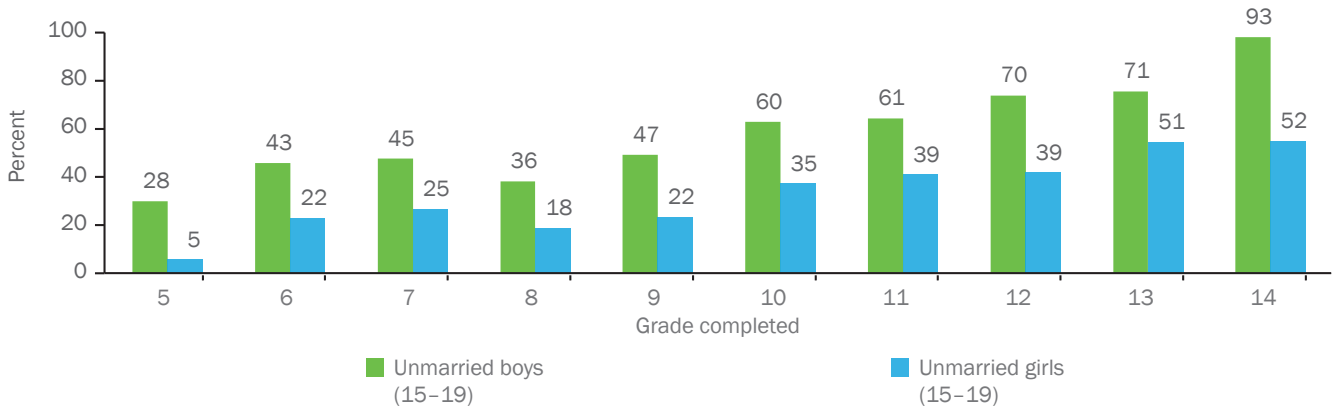

Note: [1]सांख्यिकी की विशेषताओं (धन, शहरी/ग्रामीण स्थान, जाति, धर्म और माता की शिक्षा) के लिए समीक्षा नियंत्रित है।

[2]आंकड़े केवल अविवाहित लड़कियों के हैं।

[3]सांख्यिकी विषेशताओं (पैसा, शहरी/ग्रामीण क्षेत्र, जाती, धरम और मातृत्व शिक्षा) के लिए सांख्यिकी समीक्षा का नियंत्रण–उनके लिए जिन्होंने पांच वर्ष की स्कूली शिक्षा ली है।

Figure 4: Gender disparities amongst adolescents, 15-19 years

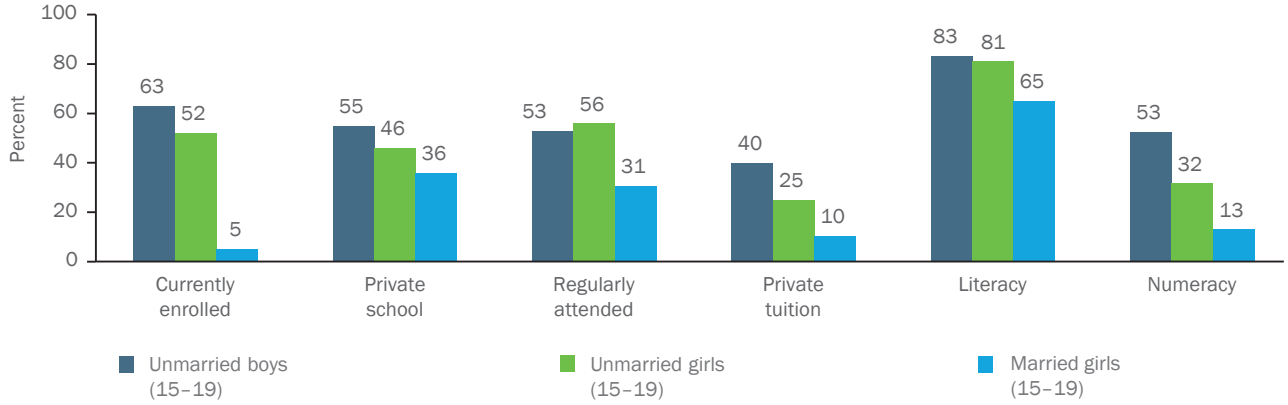

Note: वर्तमान में जो पंजीकृत हैं वह किशोरों का प्रतिशत है। निजी स्कूल में पंजीकरण उनका है जो कभी स्कूल गए ही नहीं। नियमित उपस्तिथि और निजी ट्यूशन उनमें है जो वर्तमान समय में स्कूल में पंजीकृत हैं। आंकड़ों का ज्ञान और साक्षरता उनमें है जिन्होंने आठवीं कक्षा या उससे अधिक उत्तीर्ण कर ली है।

उत्तर प्रदेश के किशोरों को शिक्षा देना: अवसर

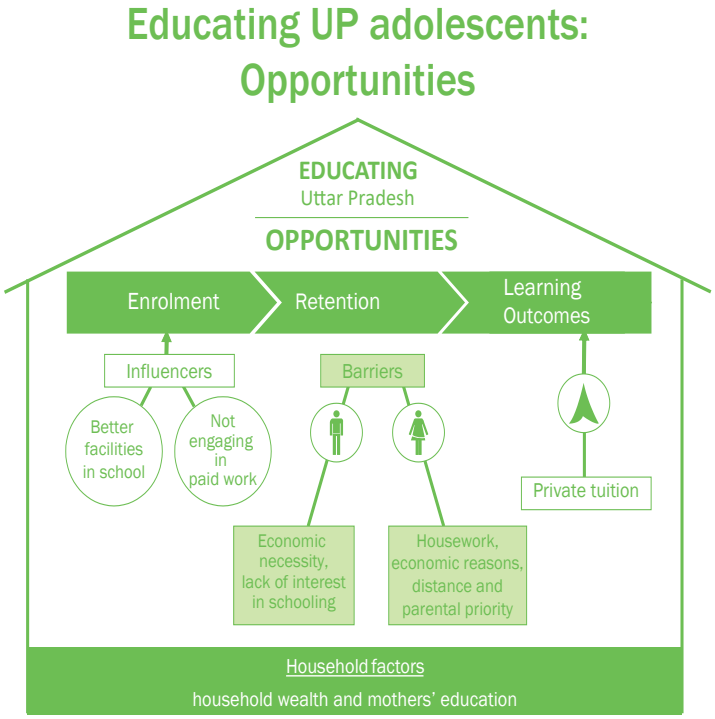

कार्यक्रम और उसकी नीतियों के बारे में

उत्तर प्रदेश में नीति बनाने वालों और कार्यक्रमों को लागू करने वालो से बातचीत में पता चला कि राज्य के लिए सीख के नतीजों को बेहतर बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, शिक्षा के स्तर में निवेश बढाकर और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर। गुणवत्ता सुधारों में शामिल है IT टेक्नोलॉजी, अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत जल्दी करना और शिक्षकों और स्कूल की सुविधाओं पर बेहतर नजर रखना। कार्यक्रम लागू करने वालों ने नोट किया कि निगरानी करने के लिए और विकास पर ध्यान रखने के लिए बेहतर आंकडों की जरुरत है ताकि राज्य, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अधिक जिम्मेदारी लें। सरकारी और निजी स्कूलों को बेहतर सुविधाएँ देने से पंजीकरण बढ़ाया जा सकता है और माध्यमिक शिक्षा में विद्यार्थियों को रोका जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने और आर्थिक बाधाएं हटाने में अभी भी बड़ा फासला है—जो इस बात का संकेत है कि माध्यमिक शिक्षा की विषय—वस्तु और उसके ढांचे—दोनों का आंकलन फिर से होना चाहिए।

जो सीखने वाले अपने परिवार में पहली पीढ़ी है, उनमें निवेश करिये

26% से अधिक अविवाहित किशोर वह थे जो अपने परिवार में पहले सीखने वाले थेः न तो उनकी माताएं और न ही पिता ने कोई शिक्षा प्राप्त करी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिन किशोरों की माताएं स्कूल गयी थीं वह अधिक शिक्षा लेते हैं, इसीलिये इस समूह के बच्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए। योजनाओ, प्रोत्साहन और मीडिया के संदेशों को इस बात को उजागर करना चाहिए कि आज के परिवारों के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए और राज्य के विकास के लिए इस पहली पीढ़ी के इन शिक्षाार्थीयों का कितना महत्व है।

संस्तुतियां

माध्यमिक शिक्षा में निवेश करिये

2017—18 में बजट का आवंटन मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा को था, और माध्यमिक शिक्षा में इससे काफी कम था[3]। यह देखते हुए कि अधिकांश बच्चे प्राथमिक स्कूल के बाद स्कूल छोड़ते हैं, माध्यमिक शिक्षा में संसाधन बढ़ने की आवश्यकता है ताकि पंजीकरण बढे, विद्यार्थी स्कूलों में बने रहें और गुणवत्ता बढे।

स्कूल की सुविधाओं में सुधार हो

स्कूलों में सभी सुविधाएँ (पीने का पानी, साफ शौचालय, खेल का मैदान और पुस्तकालय) देने के लिए RMS। के प्रावधानों

को लागू करना अति–आवश्यक है। 20% से भी कम किशोरों ने रिपोर्ट किया कि वह ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ चारों सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यदि सुविधाएँ हैं तो अधिक सम्भावना है कि बच्चे स्कूल में पंजीकृत होंगे, जो इस बात को दर्शाता है कि अवसंरचना में निवेश अति–आवश्यक है।

शिक्षा की गुणवत्ता बढे और पाठयक्रम में बदलाव का समर्थन हो

यह देखते हुए कि निजी ट्यूशन लेने वाले विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, स्कूल में दी जा रही शिक्षा के स्तर को बढाकर सीख के नतीजों में सुधार हो सकता है। भारत में जो संकेत मिलते हैं उनसे लगता है कि निम्न में यह सब शामिल कर सकते हैं:

ए) पाठ्यक्रम में कुछ नवीन बदलाव करना ताकि यह सुनिश्चित हो कि विद्यार्थियों के पास जो सामग्री है वह उनके सिखने के लिए उचित है।[4]

बी) चल रही पहलों को और बढ़ाना ताकि अतिरिक्त शिक्षकों के द्वारा अतिरिक्त समर्थन मिल सके और शिक्षकों[5,6] और स्वयं–सेवकों के माध्यम से बेहतर शिक्षा प्राप्त हो[7,8]

सी) विद्यार्थी के प्रदर्शन से शिक्षक के लिए प्रलोभन की शुरुआत करना।

डी) *ICT* –आधारित सीख[7,10] और

इ) माता–पिता/समुदाय की अधिक भागीदारी ताकि स्कूल और शिक्षक अधिक जिम्मेदार बनें।[11]

पंजीकरण और स्कूल में उपस्तिथि के विरुद्ध आर्थिक और सामाजिक बाधाएं दूर करना।

उन आर्थिक मजबूरियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिनके कारण माता–पिता स्कूल भेजनेमें असमर्थ होते हैं। लड़कों को स्कूल छोड़ने से रोकना के लिए वित्तीय बोझ को कम करना होगा– राज्य के उन प्रोग्रामों के साथ जो शिक्षा की लागत कम करते हैं। लड़कियों के लिए नगद हस्तांतरण योजना के अनुभव जैसे ''धनलक्ष्मी'' और ''अपना धन, अपनी बेटी'', इस बात का संकेत हैं कि इन लाभों से लड़कियों के सपनों को पंख मिलेंगे और वह इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगी। आगे कार्यान्वयन में लाभों को बदलना होगा, और सरल प्रक्रियां बनानी होंगी जो सबसे संवेदनशील बच्चों पर ध्यान देती हैं और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को पढाई छोड़ने से रोकना होगा, और शादी की उम्र बढ़ानी होगी।[12,13] आगे, किशोरों और उनके परिवारों के लिए उपस्तिथि के लिए कोई पुरस्कार या लाभ प्रदान करके नियमित रूप से स्कूल में उपस्तिथि को एक प्राथमिकता बननी चाहिए।

नियमित रूप में स्कूल जाने को प्रोत्साहन

नियमित रूप से स्कूल जाना एक प्राथमिकता बनाई जानी चाहिए– कुछ मध्यस्थता करके, जैसे कम लागत वाले लाभ देना, शिक्षकों की निगरानी, उन्हें पेट की सफाई की गोलियां देकर, उन्हें कुछ पोषक गोलियां देकर और उनके माता–पिताओं को स्कूल की प्रबंधन समिति से मिलवाकर।[11,14]

लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा के प्रति माता–पिता का सजग करना और इसका उत्सव मनाना

लड़कियों के पंजीकरण और स्कूल पर ध्यान देने के लिए उनके परिवार का समर्थन होना बहुत आवश्यक है। बढ़ी हुई सामाजिक जागरूकता और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन और टेलीविजन पर आधारित निवेश से ऐसे सामाजिक मानदंडों को बढ़ावा मिलता है जो लड़कियों की शिक्षा को बहुत जरूरी समझते हैं। साथ ही इन प्रयासों के असर का आंकलन करना आवश्यक होगा।

Acknowledgements

The authors are grateful to Stephanie Psaki, Priya Nanda, and Diva Dhar for insightful comments on earlier versions of this brief; to Tripti Pant Joshi for the landscaping report; and to the Bill & Melinda Gates Foundation and the David & Lucile Packard Foundation for financial support for UDAYA.

This brief is based on data collected by the UDAYA study, the report of which is available at www.projectudaya.in.[2] For more information about the Population Council's global work in education, please see our website (http://www.popcouncil.org/research/girls-education).

POPULATION COUNCIL
Ideas. Evidence. Impact.

UDAYA
TOWARDS ADULTHOOD

References

1. Ministry of Human Resource Development (MOHRD). 2016a. Educational Statistics at a Glance. New Delhi: Department of School Education and Literacy, Government of India.
2. Santhya, K.G., R. Acharya, N. Pandey et al. 2017. Understanding lives of adolescents and young adults (UDAYA) in Uttar Pradesh. New Delhi: Population Council.
3. Uttar Pradesh 2017–18. Budget Speech. Accessed on 5 October 2017 at http://budget.up.nic.in/budgetbhashan/budgetbhashan2017_2018.pdf.
4. Banerjee, A., R. Banerji, J. Berry et al. 2016. Mainstreaming an effective intervention: Evidence from randomized evaluations of "Teaching at the Right Level" in India. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 22746, Accessed on 11 August 2017 at http://www.nber.org/papers/w22746.pdf.
5. Chin, Aimee. 2005. "Can redistributing teachers across schools raise educational attainment? Evidence from operation black-board in India," Journal of Development Economics 78(2): 384–405.
6. Muralidharan, K. and V. Sundararaman. 2013. "Contract Teachers: Experimental Evidence from India," National Bureau of Economic Research Working Paper No. 19440, Accessed on 11 August 2017 at http://www.nber.org/papers/w19440.
7. Banerjee, A., S. Cole, E. Duflo et al. 2007. "Remedying education: evidence from two randomized experiments in India," The Quarterly Journal of Economics 122(3): 1235–64.
8. Lakshminarayana, R., A. Eble, P. Bhakta et al. 2014. "The support to rural India's public education system (STRIPES) trial: a cluster randomised controlled trial of supplementary teaching, learning material and material support," PLoS One 8 (7): ISSN1932-6203 (http://eprints.lse.ac.uk/51382/).
9. Muralidharan, K. and V. Sundararaman. 2011. "Teacher Performance Pay: Experimental Evidence from India," Journal of Political Economy 119(1): 39–77.
10. Linden, Leigh L. 2008. "Complement or substitute? The effect of technology on student achievement in India," JPAL working paper, Accessed on 11 August 2017 at https://www.povertyactionlab.org/evaluation/complement-or-substitute-effect-technology-student-achievement-india.
11. Santhya, K. G., A. J. Francis Zavier, P. Patel et al. 2016. Engaging Parents to Promote Girls'

    Transition to Secondary Education: Evidence from a Cluster Randomised Trial in Rural Gujarat, India. New Delhi: Population Council.
12. Nanda, P., P. Das, N. Datta et al. 2016. "Making change with cash? Impact of a conditional cash transfer program on girls' education in India" in Impact on Marriage: Program Assessment of Conditional Cash Transfers. Washington DC: ICRW.
13. Sekher, T.V. and F. Ram. 2015. Conditional Cash Transfers for Girls in India: Assessment of a Girl Child Promotion Scheme from Beneficiary Perspective. Mumbai: International Institute for Population Sciences (IIPS).
14. Jejeebhoy, S.J. 2017. Supporting Transitions from Adolescence to Adulthood: Evidence-informed Leads for Investment. New Delhi: Bill and Melinda Gates Foundation.

Study supported by

BILL & MELINDA GATES foundation

the David & Lucile Packard FOUNDATION

The Population Council confronts critical health and development issues—from stopping the spread of HIV to improving reproductive health and ensuring that young people lead full and productive lives. Through biomedical, social science, and public health research in 50 countries, we work with our partners to deliver solutions that lead to more effective policies,programs, and technologies that improve lives around the world. Established in 1952 and headquartered in New York, the Council is a nongovernmental, nonprofit organization governed by an international board of trustees.

Suggested Citation

Desai, S, and N Pandey. 2017. *Ensuring adolescents in Uttar Pradesh stay –and learn – in school. Policy Brief.* New Delhi: Population Council.

Population Council
Zone 5A, Ground Floor
India Habitat Centre, Lodi Road
New Delhi, India 110 003
Phone: 91-11-24642901
Email: info.india@popcouncil.org
Website: www.popcouncil.org

© 2017. The Population Council, Inc.